(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां से (घ) नांगल स्थित कारखाने में सोडा-ऐश और अमोनियम क्लोराइड उर्वरक का उत्पादन करने वाली इस कम्पनी के अनुसार अमुनियम क्लोराइड उर्वरक पर से नियंत्रण हटा लेने और बाद में इमदाद (सब्सीडी) बंद कर देने के परिणाम स्वरूप इसको पहले से भी ज्यादा घाटा हो सकता हैं । इस संबंध में कंपनी और राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन दिया हैं । चूंकि यह कंपनी राज्य सरकार की एक संयुक्त क्षेत्र कंपनी है, अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत राज्य सरकार ही इसे बन्द करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए समुचित सरकार है ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

1441. **श्री राम जेठमलानी :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इसकी कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (न कि राष्ट्रीय श्रम आयोग) ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 31-7-91 को प्रस्तुत कर दी है । इसने अनेक विधायी तथा अन्य उपायों की सिफारिश की है । इन सिफारिशों का कार्यान्वयन उनकी वित्तीय तथा सामाजिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है । इसमें अनेक मंत्रालय तथा विभाग शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकारों के परामर्श से कार्रवाई करनी है । संबंधे मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे रिपोर्ट की जांच करें और जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकारों से परामर्श करके अपने प्रस्तावों को शीघ्रता से अंतिम रूप दें ।

बेरोजगारी की समस्या

1442. **श्री राम जेठमलानी :**

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार के नए-नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद युवकों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने युवकों के नाम रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत किए गए और उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष, पृथक-पृथक रूप से कितने कितने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) 1983 तथा 1987-88 में रोजगार एवं बेरोजगारी पर किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षणों पर आधारित परिणाम 15-29 वर्ष के आयु समूह में खुली बेरोजगारी की दरों में वृद्धि दर्शाते है ।

सामान्य मुख्य (प्रिसीपल) स्तर कसौटी के अनुसार बेरोजगारों की दर 1983 में 6.2% से बढ़कर 1987-88 में 7.72% तक होने का तथा साप्ताहिक स्तर के अनुसार 7.64% से बढ़कर 8.58% होने का अनुमान लगाया गया गया है । तथापि, दैनिक स्तर कसौटी के अनुसार बेरोजगारी दरों में इसी अवधि के दौरान 12.00% से घट कर 10.07% की कमी परिलक्षित हुई है ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई हैं ।

(लाखों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	रोजगार दिए जाने वाले व्यक्तियों की सं० (यह अनिवार्य नहीं कि उनका पंजीकरण वर्ष में हुआ हों)
1988	59.63	3.29
1989	65.76	2.89
1990	65.41	2.65

Regional office of Provident Fund Commission in East Delhi

1443. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to open a Regional office of Provident Fund Commissioner in East Delhi;

(b) if so, by when a final decision is likely to be taken;

(c) what are the criteria being followed to decide opening up of new regional offices of Provident Fund Commissioners?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A Regional Office of the Employees Provident Fund Organisation is generally opened at the state headquarter or at the major industrial city of the State keeping in view the requirements of workers and the industrial development of the area.

144. [*Transferred to the 16th December, 1991*].

Impact of changes in industrial policy on Labour

1445. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have constituted a tripartite committee to consider he impact of the changes in industrial policy on labour; and

(b) if so, the details thereof and names of members and organisations represented there?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) and (b) A special Tripartite Committee has been constituted by the Government to consider the impact of the new industrial policy on the problems affecting labour and other related matters and to make appropriate recommendations. A statement on the composition of the Committee is attached.